दैनिक जागरण

स्थायी शांति के लिए कभी-कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है

भयावह क्षति

जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 40 जवानों की शहादत वज्रपात सरीखी है। भीषण आतंकी हमले के जरिये आतंकियों ने देश के मान-सम्मान को सीधी चुनौती है। जम्मू-कश्मीर में सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बलों ने इसके पहले इतनी अधिक क्षति का सामना कभी नहीं किया। इस हमले के बाद देश के नेतृत्व के साथ आम लोगों का रोष-आक्रोश से भर उठना स्वाभाविक है। जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शत्रु से बदला लिया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, लेकिन रोष-आक्रोश के इन क्षणों में इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर आतंकियों के दुस्साहस का निर्णायक तरीके से दमन कैसे किया जाए? इस पर गंभीरता से विचार इसलिए होना चाहिए, क्योंकि उड़ी में आतंकी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के वैसे नतीजे नहीं मिले जैसे अपेक्षित थे। वास्तव में जैश और लश्कर सरीखे आतंकी संगठनों को समर्थन-संरक्षण देने वाला पाकिस्तान जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने की कीमत नहीं चुकाता तब तक न तो उसकी सेहत पर असर पड़ने वाला है और न ही उसकी भारत विरोधी हरकतें बंद होने वाली हैं। सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने का काम चाहे जिस आतंकी संगठन ने किया हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसे सीमा पार से शह-समर्थन मिलने के साथ ही सीमा के अंदर भी किसी न किसी तरह की मदद मिली होगी। यह ठीक नहीं कि तमाम सक्रियता और सजगता के बावजूद न तो सीमा पार आतंकियों को पालने-पोसने वालों को सबक सिखाया जा पा रहा है और न ही सीमा के अंदर के ऐसे ही तत्वों को।

निःसंदेह इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उन्हें निशाना बनाने वालों से ढंग से बदला लिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ यह भी देखने की जरूरत है कि सतर्कता-सजगता में कहां कमी रह गई, जो आतंकी इतनी भीषण वारदात करने में सक्षम हो गए। आखिर कोई न कोई तो चूक हुई होगी। जब हमारे जवान कश्मीर में युद्ध सरीखे हालात से दो-चार हैं तब इस पर कहीं गहनता से विचार होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा में बार-बार कोई न कई कमी कैसे सामने आ जाती है? ध्यान रहे उड़ी, पठानकोट, कठुआ, जम्मू आदि में सैन्य या फिर अर्द्ध सैनिक बलों के ठिकानों पर हुए हमलों के बाद यही सामने आया कि सुरक्षा-सतर्कता में कमी रह गई थी। आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों-संरक्षकों को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में अपने जवानों की सुरक्षा की नए सिरे समीक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से समझौता करने के लिए जिस तरह लालायित है उससे यह साफ है कि उसने इन बर्बर आतंकियों के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही उन्हें पोषण देने वाले पाकिस्तान की अनदेखी करने का मन बना लिया है। अमेरिका का मौजूदा रवैया न केवल तालिबान, बल्कि पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने वैसे आतंकियों को बल प्रदान करने का काम और तेज कर सकता है जैसे आतंकियों ने जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर भीषण हमले को अंजाम दिया।

गजब की सियासत

इस समय देश में गजब की सियासत देखने को मिल रही है। राज्य में कुछ और दिल्ली में कुछ और। ऐसी अजब-गजब राजनीति देश में शायद पहली बार हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी (आप) के धरना मंच से यह नहीं कहतीं कि हमलोग बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में हम सब साथ रहेंगे। आखिर इस सियासत का संदेश क्या है? क्या राजनेता आम जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? वे जैसे चाहेंगे लोग उनके बहकावे में आकर उसी ओर भेड़चाल चलने लगेंगे? शायद ऐसा ही है। तभी तो सूबे में एक-दूसरे को गाली देने वाले नेता दिल्ली में एक-दूसरे से गले मिल रहे हैं। इस राजनीति में कांग्रेस जैसे दल की काफी किरकिरी हो रही है। अभी बुधवार की ही बात है। ममता बनर्जी की यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ममता ने लोकसभा में कांग्रेस के रवैये को लेकर सोनिया के समक्ष नाराजगी जताई। इस पर सोनिया गांधी ने जवाब दिया, 'हम भले ही एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपस में हम दोस्त हैं।' इसके बाद ममता ने सोनिया से कहा है, 'हम यह बात याद रखेंगे।' बुधवार को संसद सत्र के आखिरी दिन बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद अधीर चौधरी ने लोकसभा में चिटफंड प्रकरण को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि इस घोटाले की वजह से लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई है। जब अधीर तृणमूल पर बरस रहे थे तब भाजपा के सांसद मेज थपथपा कर अधीर के बयान का समर्थन कर रहे थे। बताया जाता है कि यह बात ममता को नागवार गुजरी। इसी की शिकायत ममता ने सोनिया से की। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब चिटफंड मामले को लेकर कांग्रेस ने तृणमूल पर निशाना साधा हो। इससे पहले 2016 में राहुल गांधी ने भी भ्रष्टाचार के इस मामले के तार ममता बनर्जी से जुड़े हुए बताए थे।

मनचाहा नतीजा निकालने की सुविधा

एनके सिंह

कैग रिपोर्ट सेना की जरूरतों के प्रति उपेक्षाभाव, बांझ ईमानदारी और यथास्थितिवादी सरकारी प्रवृत्ति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है

तर्क-शास्त्र में एक बहुचर्चित दोष पढ़ाया जाता है। यह इस बारे में है कि चुनिंदा तथ्यों के जरिये अपनी बात कैसे सिद्ध की जाए। राफेल सौदे को लेकर ऐसा ही किया जा रहा है। ऐसा करते समय वायु सेना की जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट में वे सभी तथ्य हैं जिनसे आप अपनी भावना के अनुरूप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर नकारात्मक निष्कर्ष पर जोर देना चाहें (जैसा कि कैग की ओर से पेश रपट के 125वें पेज में वर्णित है) तो राफेल बनाने वाली दासौ कंपनी तो छोड़िए, दूसरी सबसे कम कीमत पर विमान देने वाली कंपनी को भी खारिज कर देना चाहिए था। यानी हथियार न होने से कमजोर होती वायु सेना को अच्छे किस्म के युद्धक विमान उपलब्ध कराने के 15 साल से चल रहे प्रयास पर एक बार फिर पानी फेर दिया जाता और वह भी तब चीन भारत सीमा में घुसकर चहलकदमी करते हुए जब-तब आंखे दिखाता रहता हो और पाकिस्तान तमाम मुसीबतों के बावजूद भारत को सबक सिखाने की सनक पाले हुए हो। कैग रिपोर्ट भारत की तमाम सरकारों की सेना की जरूरतों के प्रति उपेक्षाभाव, बांझ ईमानदारी और यथास्थितिवादी सरकारी प्रवृत्ति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है।

ईमानदार माने जाने वाले रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मार्च 2012 में विमान खरीद की एक नई प्रक्रिया शुरू की, शायद यह मानते हुए कि सैन्य खरीद में लगे सरकारी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके तहत 2007 में राफेल को हर तरह से उपयुक्त पाया गया, लेकिन किसी फैसले पर पहुंचने के पहले एक स्वतंत्र समिति गठित कर दी गई। यह समिति गैर-सरकारी रक्षा विशेषज्ञों की थी। सारे पहलुओं की जांच के बाद इस समिति ने पाया कि कुछ भी गलत नहीं है और राफेल खरीद में आगे बढना चाहिए, लेकिन ईमानदारी कई बार बांझ होती है। इस समिति की रिपोर्ट आने के चंद दिनों के अंदर ही रक्षा मंत्री ने एक और टीम गठित की। यह टीम रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की थी। सरकारी अधिकारियों की मानसिकता पर गौर करें। यह टीम 25 मार्च 2015 को (यानी मोदी सरकार के आने के दस माह बाद) एक रिपोर्ट देती है कि राफेल सौदे को खारिज कर देना चाहिए और सारी प्रक्रिया और टेंडर नए सिरे से शुरू करने चाहिए। ऐसे हालात में मोदी सरकार को फैसला लेना था। जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने सक्रियता दिखानी शुरू की तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उस पर सवाल खड़े किए। ये सवाल यही अधिक बताते हैं कि बाबूराज अपनी जकड़ से कोई भी डील या अपने वर्चस्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो नकारात्मक टिप्पणी भारतीय वार्ता दल के तीन सदस्यों द्वारा की गई उसे भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि मूल रिपोर्ट में सभी सातों सदस्यों ने एक भाव से हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद कुछ लोगों ने केवल इस पर जोर दिया कि सात सदस्यीय वार्ता दल के तीन सदस्यों ने अपनी असहमति प्रकट की थी। ऐसे लोग बड़ी चतुराई से यह बात छिपा ले गए कि इन तीन सदस्यों की असहमति को खारिज कर दिया गया था। शायद इसी प्रवृत्ति के तहत रक्षा सचिव की आपत्ति को तो जाहिर किया गया, लेकिन रक्षा मंत्री की टिप्पणी को गायब कर दिया गया।

अवधेश राजपूत

कैग रिपोर्ट को गहराई से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द बेहतरीन हथियारों से लैस युद्धक विमान चाहती थी, लेकिन उसे पूरे 126 विमानों के सौदे पर मुहर लगाने में दो कठिनाई दिख रही थीं। पहली, भविष्य में तकनीक के विकास के साथ बेहतर विमान हासिल करने की संभावना और दूसरी, कम विमान लेने पर आपूर्तिकर्ता कंपनी की ओर से डिजाइन में तब्दीली को लेकर कीमत कम न करना। कंपनी कीमत इसलिए कम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी तो पूंजी लगती ही-चाहे एक विमान खरीदें या एक हजार। उधर दूसरी ओर कोई भी सरकारी अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपने स्तर पर यह फैसला ले। लिहाजा मोदी सरकार ने अंतर-सरकारी समझौता करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत विमान की कीमत वही रही जो दासौ अपनी सरकार यानी फ्रांस सरकार से लेती है। चूंकि यह सरकार से सरकार के बीच समझौता था लिहाजा बिचौलिये की गुंजाइश नहीं थी और इसी कारण इंटीग्रिटी पैक्ट की जरूरत नहीं समझी गई, लेकिन इसकी व्याख्या इस रूप में की जा रही है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश जानबूझकर छोड़ दी गई। पता नहीं क्यों, ऐसी व्याख्या करने वालों ने इसकी अनदेखी करना जरूरी समझा कि रूस और अमेरिका से भी जो अंतर सरकारी समझौते हुए उनमें भी इंटीग्रिटी पैक्ट आवश्यक नहीं समझे गए?

कैग ने अपनी रिपोर्ट की भूमिका में अपनी निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। रक्षा मंत्रालय को 5 फरवरी, 2019 को एक पत्र लिख कर कहा गया कि कैग इस बात को खारिज करते हैं कि कीमतों के बारे में रिपोर्ट में कोई काट-छांट की जाए। यह कभी नहीं हुआ और इससे रिपोर्ट बेमानी हो जाएगी। इस पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पुरजोर तरीके से कहा कि किसी भी तरह राफेल और उस पर लगे उपकरणों के वाणिज्यिक पहलू की चर्चा इस रिपोर्ट में न आए। पता नहीं इसकी क्या जरूरत थी? जो भी हो, कैग के अनुसार पूरी खरीद में छह पैकेज और 14 आइटम हैं। इन 14 आइटमों में से सात में सरकार ने ज्यादा कीमत दी जबकि चार में कम और तीन में पूर्ववत। कुल मिलाकर पहले से कम पैसे में सौदा हुआ। कैग के अनुसार संप्रग सरकार के सौदे के मुकाबले राफेल खरीद 2.86 प्रतिशत सस्ती रही।

कांग्रेस को कैग की इस रपट पर भरोसा नहीं। पहले उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया था और अब कैग के आकलन को खारिज कर दिया। आम तौर पर अगर किसी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया तो वह मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए, पर कांग्रेस इस मसले को जिंदा रखने की जिद पकड़े है। जब तथ्यों की अनदेखी की जा रही हो तो फिर इस तरह की जिद का कोई इलाज नहीं। कांग्रेस राफेल सौदे के जरिये मोदी सरकार पर नकेल कसने की रस्सी ढूंढ रही है तो भाजपा राष्ट्रवाद। ऐसा लगता है कि कोई भी यह देखने को तैयार नहीं कि वायु सेना 15 साल बगैर जरूरी युद्धक सामग्री के कैसे रही? हमारे राजनीतिक वर्ग को जानना चाहिए कि राफेल सौदे में पीएमओ के बीच में आने का कारण क्या था? आखिर इतने अहम मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए था? राजनीतिक वर्ग को अंतर-सरकारी समझौते की शर्तें भी देखनी चाहिए। इनका प्रावधान संप्रग-2 के समय की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2013 के पैरा 71 और 75 में शामिल है। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी किया है। जो इंटीग्रिटी पैक्ट हटाया गया उसका भी प्रावधान भी 2013 रक्षा सौदे की प्रक्रिया में उपलब्ध अधिकार के तहत हुआ।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मोदी के मुकाबले कौन

सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर जिस निरंकुशता का हथियार चलाकर आपात स्थिति लगाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, सत्ता में आने के लिए उनके पौत्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों वैसा ही कुछ उपक्रम करते प्रतीत हो रहे हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने भय का सहारा लिया था, राहुल गांधी झूठ और असभ्य भाषा का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका वाड्रा को राजनीति के मैदान में उतार तो दिया, लेकिन इसका एक परिणाम यह हुआ है कि अब उनकी ही क्षमता पर अविश्वास उभरकर सामने आ रहा है। पूर्व विदेश मंत्री एमएस कृष्णा ने एक हालिया कार्यक्रम में कहा कि मात्र सांसद होते हुए भी राहुल गांधी डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में जिस तरह हस्तक्षेप करते थे उससे ऊब कर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। वहीं जिस प्रकार से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति में इजाफे के खुलासे हो रहे हैं उससे नेपथ्य से कांग्रेस और सरकार के कामों में उनके हस्तक्षेप की बात भी साफ होती है। स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में प्रियंका का दबाव बढ़ेगा। सवाल है कि क्या यह कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेगा या पारिवारिक कलह का कारण बनेगा?

वर्ष 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें 'मौत का सौदागर' कहकर जिस अभियान की शुरुआत की थी उसकी निरंतरता बनी हुई है और उसका लाभ भी मोदी को मिल रहा है। तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में भी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने जो रैली की उसमें भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से चौकीदार चौर है के नारे लगवाकर यह साबित कर दिया कि कुत्सित अभिव्यक्ति का उनका सिलसिला जारी रहेगा। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के लिए एक दिवसीय अनशन पर बैठे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र भवन में स्थापित नंदी की प्रतिमा पर यह वाक्य लटकाकर कि 'जिस चाय बेचने वाले को झूठे कप-प्लेट पकड़ाना चाहिए था उसे जनता ने देश पकड़ा दिया' यह साबित कर दिया कि चाहे कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हों, चंद्रबाबू नायडू हों या अन्य नेता, वे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कुत्सित भाषा के प्रयोग को अभी और परवान चढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक इस प्रकार का अभियान मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही सहायक हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करने के राहुल गांधी के प्रयास की सफलता का आकलन है तो 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व देवरिया से खाट पंचायत शुरू करने के बाद जिस तरह लखनऊ पहुंचते-पहुंचते वह साइकिल के कैरियर पर बैठ गए थे उसी स्मृति को ताजा कर परिणाम निकाला जा सकता है। गत दिनों जिन प्रियंका वाड्रा को स्थापित करने के लिए लखनऊ में रैली हुई थी उसमें वह मौन रहीं। इससे विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता अवश्य निराश हुए होंगे जो उन्हें देखने के साथ सुनना भी चाहते थे।

बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली और पटना में मंचीय एकता दिखाने के लिए खड़े होने वालों की संख्या में जो गिरावट आई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए भाजपा विरोधी दल तैयार नहीं हैं और महागठबंधन में जो अलग-अलग दिशाओं

राजनाथ सिंह सूर्य

मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी उपक्रम यह धारणा दृढ़ कर रहा कि मोदी का कोई विकल्प नहीं

से आकर शामिल हुए थे उन्होंने पहले अपने-अपने घरों को मजबूत करने के लिए रणनीति अपना ली है। उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस का साथ लेने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार कर्नाटक में अपने से चौथाई संख्या वाले दल के नेता को कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने को विवश होना पड़ा कुछ उसी प्रकार उसे पश्चिम बंगाल में माकपा से समझौता करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस का द्रमुक के साथ समझौता जरूर है, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी, यह सामने आना बाकी है। यही स्थिति लगभग बिहार की भी है। देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई भी दल खड़ा होने को तैयार नहीं है। जाहिर है मोदी विरोधी राजनीतिक एकजुटता वर्चस्व के अहंकार से ग्रस्त होने के कारण तार-तार हो रही है। भाजपा विरोधी यह आकलन पेश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, लिहाजा मोदी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में क्षेत्रीय दल सहयोग कर सकते हैं। इसका असर सत्तारूढ़ भाजपा में निजी महत्वाकांक्षाओं के टकराव रूप में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अन्य अनेक झूठ और अफवाहों के समान इसे भी हवा देने का प्रयास किया जा रहा है।

ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती या अखिलेश यादव के सत्ता में रहने के दौरान हुए घोटालों के खुलासे से देश के जनमानस को भ्रमित करने का प्रयास यह कहकर किया जा रहा है कि यह सब चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है। इसकी आड़ में भाजपा विरोधी दल और खासकर कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संस्थाओं यथा सर्वोच्च न्यायालय, कैग, चुनाव आयोग और सेना के खिलाफ देश में अविश्वास की लहर फैलाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर भाजपा का यह प्रचार भी जोर पकड़ रहा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप से ग्रस्त हैं उन्हें लालू यादव के समान अपना जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र में बिचौलियों के खत्म होने से भ्रष्टाचार के उन्मूलन से बौखलाए लोग भी मोदी विरोधी अभियान में सक्रिय हैं। संभवतः ये वही हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि ऐसे हजारों एनजीओ जो विदेशी सहायता से विकास कार्यों में बाधक बन रहे थे, हिसाब मांगने पर कारोबार बंद कर चुके हैं।

बहरहाल अभद्र भाषा की बौछार और बदनाम करने के लिए साजिशों के नए-नए अवतार के बावजूद तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और उनकी विश्वसनीयता का कोई क्षरण नहीं हुआ है। जैसे-जैसे यह अभियान बढ़ता जा रहा है, एक प्रश्न भी जनमानस को कुरेदने लगा है कि यदि मोदी नहीं तो कौन देश को आगे ले जाने का काम करेगा? इसका जवाब देने के लिए विपक्षी चाहे जो उपक्रम कर रहे हों, जनमानस में यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई नहीं। क्या इस धारणा का लाभ अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिलेगा या अफवाहों के सहारे विरोध को मजबूत करने वाले सफल होंगे? 2019 के चुनाव का मुख्य मुद्दा यही होगा कि 'मोदी बनाम और कौन'।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम

प्रेम एक खूबसूरत और कोमल अहसास है। प्रेम रिश्तों की गर्माहट का स्नेहपूर्ण स्पर्श है। प्रेम ऊर्जा है, जीवन का आधार है। प्रेम अमूर्त है, शाश्वत है। प्रेम दया, स्नेह और सहयोग के भावों का समुच्चय है। ओशो से जब एक बार पूछा गया कि प्रेम क्या है तो मासूमियत के साथ उत्तर देते हुए उन्होंने कहा-प्रेम परमात्मा है। शायद ही दुनिया में कोई जीव हो, जो प्रेम का भूखा न हो। प्रेम इंसान की बुनियादी जरूरत है। प्रेम लोगों को आपस में जोड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया ही प्रेम पर टिकी है।

अगर मनुष्यों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम-भाव न होता तो शायद इस सृष्टि का अंत उसके आरंभ में ही हो गया होता! दरअसल एक-दूसरे के प्रति समाहित प्रेम-भाव ने ही समाज में स्थायित्व कायम किया हुआ है। प्रेम मनुष्य को अहिंसा एवं मानवता के रास्ते पर चलना सिखाता है और उसमें संवेदना, संस्कार और सहनशीलता का भाव विकसित करता है। प्रेम के बल पर न सिर्फ किसी व्यक्ति का हृदय, अपितु संपूर्ण दुनिया जीती जा सकती है। श्रद्धा, भरोसा और विश्वास से प्रेम की गांठ मजबूत होती है, जबकि ईर्ष्या, स्वार्थ और अहम इसकी कमजोर कड़ी हैं। प्रेम लोगों को एक-दूसरे के करीब लाता है और उनमें एक-दूसरे के सामान्य हितों की रक्षा का भाव जगाता है। प्रेम अगर निःस्वार्थ हो तो जीवन मधुर हो जाता है। सच्चा प्रेम लोगों को ईमानदार बनाता है। माता-पिता, बड़ों और शिक्षकों के प्रति प्रेम इंसान को जीवन की हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रेम एवं विश्वास का अभाव आपसी रिश्तों में खटास उत्पन्न करता है। दुनिया की अनेक समस्याओं का उद्भव प्रेम के अभाव में हुआ है। अगर दुनिया की दो प्रमुख समस्याओं-जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को देखा जाए तो इसका समाधान भी प्रेम में ही निहित है। मनुष्यों का प्रकृति, मातृभूमि और मानवता से प्रेम-भाव में ही इन समस्याओं का समाधान छिपा है। बदलते दौर में व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता की वजह से प्रेम का दुरुपयोग भी बढ़ा है। अतः जरूरी है कि सच्चे प्रेम और दिखावे के प्रेम में निहित अंतर को समय रहते समझा जाए और सही निर्णय लेकर जीवन को बदहाल होने से पूर्व बचा लिया जाए।

सुधीर कुमार

संसद के केंद्रीय कक्ष में 'अटलजी'

अरविंद कुमार सिंह

केंद्रीय कक्ष में भारत के स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रनिर्माण के महान नायकों की तस्वीरें प्रेरणा देती हैं

संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद तैलचित्र का अनावरण किया। अटलजी ने 10 बार लोकसभा में और दो बार राज्यसभा का सदस्य रहने के साथ अपने लंबे राजनीतिक जीवन में भारतीय संसद पर अमिट छाप छोड़ी। दरअसल केंद्रीय कक्ष में स्वाधीनता संग्राम के चंद दिग्गज लोगों की ही तस्वीरें लगी हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष को तीसरा सदन कहा जाता है इसका गुंबद विश्व के भव्यतम गुंबदों में एक माना जाता है। भारत के इतिहास में इसकी खास जगह है, क्योंकि यहीं 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन ने भारत को सत्ता हस्तांतरित की थी। भारतीय संविधान की रचना भी केंद्रीय कक्ष में ही हुई। तमाम दिग्गज नेताओं की दिनचर्या में इस जगह का अपना अलग महत्व है।

आरंभ में केंद्रीय कक्ष का उपयोग केंद्रीय विधान सभा और राज्यसभा के पुस्तकालय के रूप में होता था। बाद में 1946 में इसका स्वरूप बदला और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया। 9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक यहीं संविधान सभा की बैठकें हुईं और अहम फैसले लिए गए। बाद में केंद्रीय कक्ष का उपयोग दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाने लगा। लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ होने पर और हर साल पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इसी तरह केंद्रीय कक्ष का उपयोग विदेशी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संसद सदस्यों को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। यहां कई बड़े आयोजन भी हो चुके हैं, लेकिन इस कक्ष में लगे तैल चित्रों का भी अपना खास इतिहास है।

केंद्रीय कक्ष में भारत के स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रनिर्माण के महान नायकों की तस्वीरें प्रेरणा देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें एकाध अपवाद को छोड़ दें तो बाकी सभी चित्र भेंट में मिले हैं और सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। अटलजी के इस चित्र को भी लोक अभियान संस्था ने भेंट किया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल हैं। अटलजी ही नहीं यहां अधिकतर चित्रों का अनावरण राष्ट्रपति के हाथ ही हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में सबसे अधिक तैल चित्र केंद्रीय कक्ष में लगे।

दरअसल केंद्रीय कक्ष या संसद परिसर में कौन-सा चित्र या प्रतिमा लग सकती है, इसका इसका फैसला संसद की राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्रों और प्रतिमाओं को लगाने संबंधी समिति लेती है। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली इस समिति में दोनों सदनों के प्रमुख दलों के कई बड़े नेता शामिल हैं। अटलजी के तैलचित्र संबंधी फैसले भी इसी समिति ने लिया। समिति ने माना कि वाजपेयी जैसे लोकतंत्र के महारथी के चित्र के बिना संसद का केंद्रीय कक्ष अधूरा है।

केंद्रीय कक्ष में सबसे अहम स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। इस तरह देखें भारत के इतिहास के तमाम सितारों के बीच अब अटलजी को भी जगह मिली है। जाहिर है कि इससे भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

(लेखक संसदीय मामलों के जानकार हैं)

मेलबाक्स

ग्रामीण शिक्षा का सही विश्लेषण

ग्रामीण शिक्षा की खराब सेहत शीर्षक से प्रकाशित ऋषभ कुमार मिश्र का लेख शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं की आंखें खोलने वाला है। सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों का अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा भाव रखना शिक्षा की गिरती गुणवत्ता का कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम राय बनती जा रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, केवल मिड डे मील, किताब, ड्रेस और वजीफा ही मिलते हैं। सारा दिन विद्यालयों में बच्चे इधर-उधर दौड़-भाग करते रहते हैं। देर-सबेर आने वाले शिक्षक मिड डे मील का बंदोबस्त करके निश्चिंत हो जाते हैं। ग्राम प्रधान को केवल मिड डे मील के कमीशन से मतलब होता है। शिक्षक और प्रधान का यह गठजोड़ लाभ केंद्रित है। वहीं गरीब बेसहारा बच्चों के विकास के लिए ग्रामीण शिक्षा समिति भी कोई कोशिश नहीं करती। जब तक ध्येयनिष्ठ सरकारी शिक्षक एवं अधिकारी कमर नहीं कसेंगे और बच्चों के विकास के लिए समर्पित नहीं होंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता।

राघवेंद्र त्रिपाठी, गोंडा

नेताजी का आशीर्वाद

16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम बेला पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दिली इच्छा अंततः सबके सामने प्रकट हो गई। इसमें वह एक बार फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं। यही नहीं, इनकी इच्छा यहां तक है कि जो भी सांसद इस समय हैं वही अगली लोकसभा में भी चुन कर आए। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की और अपना आशीर्वाद भी दिया। इससे फिलहाल भाजपा के लिए मुलायम सिंह यादव का कद बढ़ गया है, जबकि विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। सपा के वरिष्ठतम नेता के द्वारा कही गई ये बातें कांग्रेस के साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी कम तनाव पैदा करने वाली नहीं हैं।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

जहरीली शराब की बिक्री

आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इसके बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। लोग जाने-अनजाने इसका सेवन कर रहे हैं। यह दुखद है कि युवाओं में शराब सेवन की लत तेजी से बढ़ रही है। शराब का सेवन चाहे किसी भी लिंग या उम्र के लोग करें, यह अंततः शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। इसके सेवन से उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक की समस्या तक उत्पन्न हो सकती है। सरकारों को इसके उत्पादन एवं बिक्री पर रोक सुनिश्चित करनी चाहिए।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

उचित सुझाव

पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कुछ समय पहले विवाह समारोहों में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सुझाव दिया था। उनके अनुसार चाय और नमकीन में भी फेरे लेकर विवाह की रस्म निभाई जा सकती है। इसके लिए लाखों रुपये फूंकने की क्या जरूरत है इत्यादि। यह सुझाव बहुत ही सराहनीय है। सरकार को इस पर गंभीरता दिखाते हुए इसे कानूनी रूप देकर जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग विवाह समारोहों में इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि बाद में उनके घर का सारा बजट ही गड़बड़ हो जाता है। वहीं बहुत से माता-पिता पैसे के अभाव में बेटियों की शादी के लिए चिंतित रहते हैं। शादियों में खर्च रुकने से किसी बेटी के माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

raju09023693142@gmail.com

प्रियंका की परीक्षा

प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में क्या राहुल गांधी का स्थान ले सक